

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 31 दिसम्बर, 2010

विषय:- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-735/3-5 दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त वर्तमान में ₹ 1,91,55,000/- (₹ एक करोड़ इक्यानब्बे लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.
- (2) उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
- (3) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.
- (4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
- (5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
- (6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
- (7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेतर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- (8) जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

- (9) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
 - (10) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
 - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
 - (12) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
 - (13) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
 - (14) विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायित/बाह्य सहायित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
 - (15) यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात् योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.
 - (16) योजना में अग्रेतर वित्तीय स्वीकृति/धनराशि अवमुक्त तभी की जायेगी जब सम्पूर्ण परियोजना/कार्ययोजना समय-योजना अवधि, कुल लागत, वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, outcome/impact के लक्ष्य/अनुमान, चयनित कार्यों का विवरण आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट/प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो.
 - (17) ऐसे सभी निर्माण कार्य जो रु० 5.00 लाख से अधिक हैं, का आगणन/प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी जाय तथा ऐसे आगणन/प्राक्कलन के सापेक्ष शासन के टी०ए०सी० वित्त विभाग से परिक्षणोपरान्त अनुमोदित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त ही इस प्रकार के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति अधीनस्थ कार्यालयों को निर्गत की जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय अनुदान सं०-27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा.
3. ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-231(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय

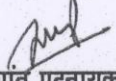
(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

संख्या- 498 (1)/X-2-2010, तदुद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशान्त पटनायक)
अपर सचिव

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	लेखा शीर्षक/योजना का नाम/मानक मद	परिव्यय	आय-व्ययक प्रावधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1	2		3	4	5
1	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 04-00-आरक्षित एवं सिविल एवं सोयम वनों का विकास 24- वृहत निर्माण		60000	50000	10000
	योग	190000	60000	50000	10000
2	06-00-वन पंचायत तथा वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों का अल्पकालीन प्रशिक्षण 02- मजदूरी 07- मानदेय 08- कार्यालय व्यय 09- विद्युत देय 18- प्रकाश 19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय 26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र 29- अनुरक्षण 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 47- कम्प्यूटर हार्डवेयर/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		100 50 50 50 50 50 130 130 100 50	50 25 25 25 25 25 65 65 50 25	50 25 25 25 25 25 65 65 50 25
	योग	20000	760	380	380
3	12-00-रिसर्च एवं टेक्नोलोजी डेवलपमेन्ट 25- लघु निर्माण कार्य 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		1000 200	500 100	500 100
	योग	30000	1200	600	600
4	13-00-वनो की सुरक्षा हेतु/अतिक्रमण रोकने के लिये बाउन्ड्रीवाल का निर्माण 15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद 23- गुप्त सेवा व्यय 25- लघु निर्माण कार्य		200 100 8000	100 50 7000	100 50 1000
	योग	50000	8300	7150	1150

5	15-00-अधिक उच्च प्राणि उद्यान, वन मनोरंजन चेतना केन्द्र एवं पर्यटक स्थलों का विकास				
	29- अनुरक्षण		3500	2500	1000
	योग	35000	3500	2500	1000
6	17-00-इको टूरिज्म				
	13- टेलीफोन पर व्यय		250	125	25
	15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद		500	250	250
	योग	30000	750	375	275
7	18-00-गूजर पुनर्वास योजना				
	42- अन्य व्यय		100	50	50
	योग	10000	100	50	50
8	25-00-जीवों के वास स्थलों का विकास				
	25- लघु निर्माण कार्य		6000	5000	1000
	29- अनुरक्षण		7000	3500	3500
	योग	70000	13000	8500	4500
9	31-00-वन अग्नि नियंत्रण हेतु जी0आई0एस0 यूनिट का गठन				
	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान		50	25	25
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय		250	125	125
	योग	8000	300	150	150
10	34-00-वन पंचायतों के सुदृढीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना				
	08- कार्यालय व्यय		100	50	50
	25- लघु निर्माण कार्य		2000	1000	1000
	योग	20000	2100	1050	1050
	योग अनुदान सं0-27	463000	90010	70755	19155

(वर्तमान स्वीकृति ₹ एक करोड़ इक्यानब्बे लाख पचपन हजार मात्र)

(सुशांत प्रटनायक)
अपर सचिव